International Journal of Multidisciplinary Trends

E-ISSN: 2709-9369
P-ISSN: 2709-9350
www.multisubjectjournal.com
IJMT 2022; 4(1): 279-282
Received: 02-01-2022
Accepted: 08-02-2022

आदर्श प्रसाद
विद्यार्थी, स्नातकोत्तर,
राजनीतिक विज्ञान विभाग,
मांडर कॉलेज मांडर, रांची
यूनिवर्सिटी, झारखण्ड,
भारत

Corresponding Author:
आदर्श प्रसाद
विद्यार्थी, स्नातकोत्तर,
राजनीतिक विज्ञान विभाग,
मांडर कॉलेज मांडर, रांची
यूनिवर्सिटी, झारखण्ड,
भारत

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: एक अवलोकन

आदर्श प्रसाद

सारांश
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उत्कृष्टता के लिए शिक्षा संस्थानों को फिर से तैयार करने पर विचार करने वाली 21वीं सदी की पहली नीति है। राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, शिक्षा राष्ट्र का भविष्य और लोगों की नियति तय करती है। इसका प्रभाव राष्ट्र और नागरिकों के विकास और प्रगति के संदर्भ में दीर्घकालिक होगा।
इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बनना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य स्कूल और उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार लाना है और इस प्रकार भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में आकार देना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) का उद्देश्य स्कूल और कॉलेज शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला और बहु-विषयक बनाकर भारत को एक जीवंत ज्ञान समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदलना है, जो 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल हो और जिसका उद्देश्य प्रत्येक छात्र की अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना हो। इस शोध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और हितधारकों पर इसके प्रभावों के बारे में पता की कौशिश की गई है। उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा पर देश की सबसे बड़ी चर्चा-आधारित डॉक्यूमेंट्री राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रतीत होती है। यह नीति विभिन्न सामाजिक स्तरों के बीच एक व्यापक, बहु-चरणीय चर्चा का परिणाम है। नीति चार आधार स्तंभों पर आधारित है।

कुटशब्द: शिक्षा, उच्च शिक्षा, एनईपी

प्रस्तावना
भारत सरकार ने 29 जुलाई, 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को मंजूरी दी गई। इस नीति ने 1986 में 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) का स्थान लिया। यह 2030 एजेंडा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा 2015 में अपनाए गए सत्रह लक्ष्यों में से चौथे सतत विकास लक्ष्य, एसडीजी4-शिक्षा को अपनाने के हिस्से के रूप में है। आज के परिदृश्य में शिक्षा की भूमिका और इसके महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर हम स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के बाद के युग की तुलना करें तो विकास और प्रगति देखी जा सकती है। 34 वर्षों के बाद भारतीय सरकार हमारे अध्ययन के तरीके को बदलने जा रही है, यह शिक्षा नीति में तीसरा संशोधन है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कई बदलाव प्रस्तावित हैं जो

निश्चित रूप से सभी हितधारकों को प्रभावित करेंगे। एनईपी 2020 के प्रावधानों और कार्यक्रमों को हमारे स्कूलों और संबंधित बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश द्वारा समर्थित होना चाहिए। अकेले नीति शिक्षा को नहीं बदलेगी यदि इसे शिक्षकों के कौशल, स्कूलों में बुनियादी ढांचे और प्रभावी शासन में आवश्यक उन्नयन के साथ पूरक नहीं किया जाता है।

राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, शिक्षा राष्ट्र का भविष्य और लोगों की नियति तय करती है। इसका प्रभाव राष्ट्र और नागरिकों के विकास और प्रगति के संदर्भ में दीर्घकालिक होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कई बदलाव प्रस्तावित हैं जो निश्चित रूप से सभी हितधारकों को प्रभावित करेंगे। भारत को वैश्विक ज्ञान शक्ति में बदलने की दृष्टि से दस्तावेज़ में बहुभाषीयता और भाषा की शक्ति को बढ़ावा देने, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान करने, सीखने के सभी स्तरों तक सार्वभौमिक पहुँच प्राप्त करने, शिक्षकों को सम्मानित करने-उन्हें सीखने की प्रक्रिया का हृदय मानने, पाठ्यक्रम में तालमेल बनाने और स्वायत्तता, सुशासन और सशक्तिकरण की गारंटी देने का वादा किया गया है। आज के परिदृश्य में शिक्षा की भूमिका और इसके महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर हम स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के बाद के युग की तुलना करें तो विकास और प्रगति देखी जा सकती है। 34 वर्षों के बाद भारतीय सरकार हमारे अध्ययन के तरीके को बदलने जा रही है, यह शिक्षा नीति में तीसरा संशोधन है।

शिक्षक शिक्षा पर सिफारिश राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के भाग II के तहत अध्याय-15 में दी गई है जो उच्च शिक्षा में नीतिगत बदलावों का विवरण देती है। इसे ग्यारह उप-बिंदुओं में विभाजित किया गया है। समस्त शिक्षक शिक्षा बहुविषयक संस्थानों में होगी। यह शिक्षक शिक्षा क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन है। शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय या शिक्षक शिक्षा संस्थान जो एकल-धारा कार्यक्रम चला रहे हैं, उन्हें चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए। "सभी बहुविषयक विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षा विभाग स्थापित करने का लक्ष्य रखेंगे, जो शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में अत्याधुनिक शोध करने के अलावा, अन्य विभागों के सहयोग से बी.एड. कार्यक्रम भी चलाएंगे" (एनपीई 2020, पृष्ठ 10)। इस का मुख्य उद्देश्य "यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षकों को सामग्री, शिक्षाशास्त्र और अभ्यास में उच्चतम गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण दिया जाए, शिक्षक शिक्षा प्रणाली को बहु-विषयक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ले जाकर, और 4-वर्षीय एकीकृत बी-एड की स्थापना करना। एनईपी 2020 के तहत स्कूल न जाने वाले लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्यधारा में वापस लाया जाएगा। एनपीई 2020 के अनुसार, शिक्षक शिक्षा संकायों में विशेष विषयों के लिए विशेष प्रशिक्षक, प्राथमिक विद्यालय के विषय क्षेत्रों के लिए सामान्यवादी विशेष शिक्षक, मध्य या उच्च विद्यालय में विषय शिक्षक शामिल हैं।

नीति में कहा गया है कि उच्च शिक्षा संस्थान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए खुद को बदलेंगे और इस प्रकार मान्यता प्राप्त करेंगे। संस्थान की मान्यता उन्हें स्वायत्तता प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा और अनुसंधान में गुणवत्ता में सुधार होगा। उन्हें उच्च स्तर की मान्यता मिलेगी, जिसके परिणामस्वरूप स्वायत्तता का स्तर भी बढ़ेगा। उच्च शिक्षा संस्थान गुणवत्ता, मान्यता और स्वायत्तता के मार्ग पर चल सकते हैं और बहु-विषयक विश्वविद्यालय बन सकते हैं। संस्थानों को हितधारकों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए स्वायत्तता पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। संस्थान की पूरी क्षमता का उपयोग करना और उन्हें समय के साथ उत्तरदायी और नवोन्मेषी बनाना। इस पत्र में भारत और विदेशों में शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित स्वायत्तता पर साहित्य की विभिन्न आयामों, दृष्टिकोणों और स्वायत्तता के स्तरों पर समीक्षा की गई है। साहित्य समीक्षा, लेखकों के अनुभव और स्वायत्त संस्थानों में काम करने वाले विशेषज्ञों के साथ बातचीत के आधार पर स्वायत्तता

प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए दिशानिर्देश बताए गए हैं। बुनियादी ढांचे का समर्थन, स्कूल छोड़ चुके बच्चों को मुख्यधारा में वापस लाने के लिए नवीन शिक्षा केंद्र, छात्रों और उनके सीखने के स्तर पर नज़र रखना, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों तरीकों को शामिल करते हुए सीखने के लिए कई रास्ते उपलब्ध कराना, स्कूलों के साथ परामर्शदाताओं या अच्छी तरह से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं का जुड़ाव, एनआईओएस और राज्य ओपन स्कूलों के माध्यम से कक्षा 3, 5 और 8 के लिए ओपन लर्निंग, कक्षा 10 और 12 के समकक्ष माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, वयस्क साक्षरता और जीवन-संवर्धन कार्यक्रम इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रस्तावित तरीके हैं।

एनपीई 2020 ने "सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में प्रशिक्षण के साथ संकाय नियुक्त करने की सलाह दी है जो स्कूली शिक्षा से सीधे संबंधित विषय जैसे मनोविज्ञान, बाल विकास, भाषा विज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के साथ-साथ विज्ञान शिक्षा, गणित शिक्षा, सामाजिक विज्ञान शिक्षा और भाषा शिक्षा कार्यक्रम। शिक्षा विभागों में संकाय प्रोफ़ाइल विभिन्न क्षेत्रों में पीएचडी के साथ विविधतापूर्ण होगी। "शिक्षा विभागों में संकाय प्रोफ़ाइल अनिवार्य रूप से विविधतापूर्ण होने का लक्ष्य रखेगी, लेकिन शिक्षण/क्षेत्र/शोध अनुभव को अत्यधिक महत्व दिया जाएगा" (एनपीई 2020, पृष्ठ 43, 15.8)।एनईपी शिक्षक तैयारी के लिए पाठ्यक्रम के कुछ प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करता है, जिनमें सुधार और पुनरुद्धार किया जाएगा, जैसे कि "बुनियादी साक्षरता/संख्यात्मकता पर ध्यान केंद्रित करना, समावेशी शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन, भारत और इसकी परंपराओं का ज्ञान, और छात्रों में 21वीं सदी के कौशल जैसे समस्या-समाधान, आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच, नैतिक और नैतिक तर्क, और संचार और चर्चा क्षमताओं का विकास"। लेकिन शिक्षक तैयारी कार्यक्रम के लिए, किसी भी अन्य पहलू से अधिक, शिक्षण कौशल वृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिसका उल्लेख एनईपी 2020 में नहीं किया गया है।

भारत में केवल शैक्षणिक रूप से सुदृढ़ शिक्षक तैयारी कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए 2023 तक घटिया और बेकार पड़े शिक्षक शिक्षा संस्थानों को बंद करने के लिए मिशन चलाया जाएगा। सभी स्टैंड-अलोन शिक्षक शिक्षा संस्थानों को 2030 तक खुद को बहु-विषयक एचईटी के रूप में परिवर्तित करना चाहिए ताकि केवल चार साल का एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम पेश किया जा सके। अगले 3-5 वर्षों के भीतर सभी टीईएल को बहु-विषयक एचईआई के रूप में अनिवार्य मान्यता दी जानी चाहिए। इस मिशन की प्रगति की निगरानी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक प्राधिकरण [एनएचईआरए] द्वारा हर 3 महीने में और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग [आरएसए] द्वारा हर 6 महीने में की जाएगी (एनईपी 2020, पृष्ठ 42, 15.5) जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा को बनाए रखने की दिशा में एक पहल सुनिश्चित करता है।

एनपीई का कहना है कि "एक तरफ चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक तैयारी कार्यक्रम में मूलभूत परिवर्तन और दूसरी तरफ निष्क्रिय संस्थानों को बंद करने के लिए, पर्याप्त नई शिक्षक तैयारी क्षमता के निर्माण की आवश्यकता होगी: संप्रदाय के लिए पर्याप्त सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता होगी। आरएसए द्वारा डिजाइन की जाने वाली विशेष योजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र में परोपकारी प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा" (एनपीई 2000, पृष्ठ 48, 18.13. और ड्राफ्ट एनपीई 2019, पृष्ठ 287, पी15.2.3.)।

एनईपी ने विश्वविद्यालयों के विभागों को शिक्षा में शोध और नवाचार के लिए स्थानों को मजबूत और विकसित करने की सिफारिश की है। "विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभागों को शिक्षा के सभी अन्य विभागों के साथ सार्थक संबंधों के माध्यम से सभी विषयों में शिक्षा कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। वे स्कूली शिक्षा में

शिक्षकों के साथ-साथ उच्च शिक्षा में शिक्षकों की सेवा-पूर्व शिक्षा और सेवाकालीन सतत व्यावसायिक विकास को पूरा करेंगे। वे शिक्षक शिक्षा के लिए संकाय भी तैयार करेंगे। उन्हें शिक्षकों के सेवाकालीन सतत व्यावसायिक विकास के लिए पाठ्यक्रम और गतिविधियाँ विकसित करनी चाहिए, और शुरुआती शिक्षकों को सलाह देने वाले कार्यक्रम पेश करने चाहिए। सभी पाठ्यक्रमों की पेशकश पूर्णकालिक कार्यक्रमों के अलावा अंशकालिक, शाम, मिश्रित और ऑनलाइन सहित कई प्रारूपों में उपलब्ध होनी चाहिए"।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली की कल्पना की गई है जो सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके हमारे राष्ट्र को स्थायी रूप से एक समान और जीवंत ज्ञान समाज में बदलने में सीधे योगदान देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षक शिक्षा परिदृश्य में बड़े बदलावों की सिफारिश करती है। प्रत्येक देश में उच्च शिक्षा ही सामाजिक स्थिति, अर्थव्यवस्था, मानव के स्वस्थ दृष्टिकोण और अपनाने को निर्धारित कर सकती है। प्रत्येक देश के शिक्षा विभाग का दायित्व है कि वह प्रत्येक नागरिक को उच्च शिक्षा प्रदान करे; जैसे-जैसे सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) बढ़ेगा। इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई। इस नीति में योग्यता आधारित प्रवेश को प्रोत्साहित किया गया और आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति और मुफ्त शिक्षा प्रदान की गई। संकाय सदस्यों का प्रदर्शन योग्यता और शोध आधारित होगा और नियामक निकायों के नेता योग्यता आधारित सिद्ध होंगे। भारतीय उच्च शिक्षा की प्रणाली अंक केंद्रित से कौशल केंद्रित, सीखने केंद्रित से अनुसंधान केंद्रित, सूचना केंद्रित से ज्ञान केंद्रित और विकल्प केंद्रित से योग्यता केंद्रित की ओर बढ़ने जा रही है। यह नीति प्रत्येक छात्र को आजीवन शिक्षा भी देती है। हमें एक ऐसी संरचना की आवश्यकता है जो न केवल शिक्षा प्रणाली में पंजीकृत बच्चों के प्रतिशत में परिणामों की पारदर्शिता और जवाबदेही स्थापित करे, बल्कि, देश के युवा 21वीं सदी में भारत को आगे बढ़ा सकते हैं, उन्हें बचपन से ही एक ठोस शैक्षिक नींव के साथ निवेश करने की आवश्यकता है।

संदर्भ

1. पंकज अरोड़ा और उषा शर्मा "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रचनात्मक सुधारों की ओर" प्रकाशक: शिप्रा पब्लिकेशंस, 2021
2. अनामिका चौहान, किरन शर्मा "नई शिक्षा नीति 2020 संभावनाएं एवं चुनौतियां" प्रकाशक: नालन्दा प्रकाशन 2021
3. अतुल कोठारी "राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भारतीयता का पुनरुत्थान" प्रकाशन: प्रभात प्रकाशन 2021
4. National Education Policy 2020. https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nep/NEP_Final_English.pdf referred on 10/08/2020
5. https://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/Draft_NEP_2019_EN_Revised.pdf
6. Teacherbadi, National Education Policy 2021: NEP New Education Policy High lights (2021), https://teachersbadi.in/national-education-policy-draft- in-telugu-send-suggestions-for-nep-draf/1/15, Accessed on 01 July 2021
7. https://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/npe.pdf
8. https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/edutrends-india/nep-2020-empowering-the-teacher/